



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 921]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 14, 2010/वैशाख 24, 1932

No. 921]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 14, 2010/VAISAKHA 24, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2010

का.आ. 1090(अ).—यतः लिब्रेशन टाईगर ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात् एलटीटीई कहा गया है) श्रीलंका स्थित एक संगठन है किन्तु इससे सहानुभूति रखने वाले, इसके समर्थक तथा कार्यकर्ता भारत के भू-भाग में फैले हुए हैं;

और यतः सभी तमिलों के लिए एक पृथक राष्ट्र (तमिल ईलम) की स्थापना का एल टी टी ई का लक्ष्य भारत की संप्रभुता एवं भू-भागीय अखण्डता के लिए खतरा है, और जिसका अर्थ भारतीय भू-भाग के एक हिस्से का भारत संघ से अंतरण या पृथक्कीकरण किया जाना है, और इस प्रकार यह विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के दायरे में आता है;

और यतः प्रतिबंध के बावजूद लिट्टे समर्थकों द्वारा जुलूसों, प्रदर्शनों आदि के जरिए लिट्टे के लिए समर्थन जुटाने एवं इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए श्रीलंका में अशांत स्थिति का अनुचित लाभ उठाया गया जिससे तमिलनाडु राज्य में अशांति पैदा हुई और राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है;

और यतः यद्यपि लिट्टे (एल टी टी ई) का श्रीलंका में काफी सीमा तक सफाया कर दिया गया है किन्तु हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि शेष बचे लिट्टे काडर/नेता, पृथक तमिल ईलम की स्थापना करने और गद्दारों (भारत सरकार) एवं शत्रुओं (श्रीलंका सरकार) से बदला लेने के अपने घोषित उद्देश्य के अनुसरण में, तमिलनाडु में पुनः संगठित हो रहे हैं। अतः इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ये शेष बचे काडर अपने पुनः संगठित कार्यकलापों के लिए एक मजबूत आधार के रूप में भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य, का प्रयोग करेंगे क्योंकि हाल ही में प्रतिबंधित कुछ एल.टी.टी.ई के काडर गुप्त रूप से समुद्री रास्ते से आए थे। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करेंगे तथा श्रीलंकाई शरणार्थियों के भेष में अपने साथ प्रामाणिक दस्तावेज लेकर आयेंगे।

और यतः इन्टरनेट पोर्टल्स पर लेखों के माध्यम से, यह डायसपोरा, एल टी टी ई की पराजय के लिए भारत के शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों को जिम्मेदार ठहराते हुए श्रीलंकाई तमिलों में लगातार भारत विरोधी भावनाएं फैला रहा है। इन्टरनेट के माध्यम से इस प्रकार के लगातार किये जा रहे प्रचार से भारत में अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

और यतः उपर्युक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लिट्टे एक विधिविरुद्ध संगम है और ऐसी सभी अलगाववादी गतिविधियों को सभी संभव उपायों से नियंत्रित करने की निरंतर सख्त जरूरत है।

और यतः केन्द्रीय सरकार के पास सूचना है कि:-

- (i) हाल ही में तमिलनाडु राज्य में तलाशे गए लिट्टे काडरों, इसे छोड़ने वालों, इससे सहानुभूति रखने वालों की गतिविधियों से पता चलता है कि तमिलनाडु में भेजे गए काडरों का अंततोगत्वा लिट्टे द्वारा विधिविरुद्ध कार्यकलापों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा;
- (ii) प्रतिबंध लागू होने के बावजूद भारत में लिट्टे समर्थक संगठनों और लोगों की गतिविधियां देखी गई हैं और इन ताकतों द्वारा लिट्टे को अपना समर्थन देने के प्रयास किए गए हैं;

- (iii) लिट्टे नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अपने संगठन के बारे में भारत की नीति और अपनी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य तंत्र की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते रहे हैं;

और यतः केन्द्र सरकार का यह मत है कि लिट्टे की उपर्युक्त गतिविधियां भारत की सम्प्रभुता और भू-भागीय अखण्डता के लिए और साथ ही लोक-व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई हैं और हानिकर हैं, इसलिए इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना चाहिए;

और यतः केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि (i) भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता के लिए हानिकर लिट्टे की सतत हिंसक एवं विध्वंसकारी गतिविधियां तथा (ii) इसके द्वारा लगातार राख्त भारत-विरोधी रुख अपनाए जाने और भारतीय राष्ट्रियों की सुरक्षा को सतत रूप से गंभीर खतरा पैदा किए जाने के कारण, लिट्टे को तत्काल प्रभाव से "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करना आवश्यक है।

अतः अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी आदेश के अध्याधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. I-11034/1/2010-आईएस. I]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2010

S.O. 1090(E).—Whereas the Liberation Tigers of Tamil Eelam (hereinafter referred to as the LTTE), is an association based in Sri Lanka but having its sympathisers, supporters and agents in the territory of India;

And whereas the LTTE's objective for a separate homeland (Tamil Eelam) for all Tamils threatens the sovereignty and territorial integrity of India, and amounts to cession and secession of a part of the territory of India from the Union and thus falls within the ambit of an unlawful activity;

And whereas, the turbulence in Sri Lanka was exploited by the pro-LTTE forces to draw up support for the LTTE and its cause by taking out processions, demonstrations, etc., in spite of the ban, causing disquiet and threat to the security of the State of Tamil Nadu;

And whereas though LTTE has been decimated in Sri Lanka but recent reports reveal that remnant LTTE cadres/leaders are regrouping in Tamil Nadu in pursuance of their avowed objective of establishing separate Tamil Eelam and wrecking revenge on the traitors (Government of India) and enemies (Government of Sri Lanka).

Possibilities of these remnant cadres using India, especially in the State of Tamil Nadu, as a rear base for their regrouping activities thus cannot be ruled out as some LTTE cadres interdicted recently, had come by clandestine sailing. Possibility of their entering India through sea route and genuine documents in the guise of Sri Lankan Tamil refugees cannot be ruled out;

And through articles in the internet portals, the diaspora continue to spread anti-India feeling amongst the Sri Lankan Tamils by holding the top Indian political leaders and bureaucrats responsible for the defeat of the LTTE. Such propaganda through internet which remains continued, are likely to impact VVIP security adversely in India;

And whereas for the reasons aforesaid, the Central Government is of the opinion that the LTTE is an unlawful association and there is a continuing strong need to control all such separatist activities by all possible means;

And whereas the Central Government has the information that –

- (i) the activities of the LTTE remnant cadres, dropouts, sympathizers who have been traced out recently in the State of Tamil Nadu suggest that the cadres sent to Tamil Nadu would ultimately be utilised by the LTTE for unlawful activities;
- (ii) the activities of pro-LTTE organisations and individuals have come to notice in India, despite the ban in force and attempts have been made by these forces to extend their support to the LTTE;
- (iii) the LTTE leaders, operatives and supporters have been inimically opposed to India's policy on their organisation and action of the State machinery in curbing their activities;

And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the LTTE continue to pose a threat to, and are detrimental to, the sovereignty and territorial integrity of India as also to the public order and, therefore, it should be declared as an unlawful association;

And whereas the Central Government is further of the opinion that (i) because of the LTTE's continued violent and disruptive activities prejudicial to the integrity and sovereignty of India; and (ii) it continues to adopt a strong anti-India posture as also continues to pose a grave threat to the security of Indian nationals, it is necessary to declare the LTTE as an "unlawful association" with immediate effect;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and the proviso to sub-section (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam (the LTTE) as an unlawful association and directs, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect on and from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. I-11034/1/2010-IS.1]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.